श्री सुरेश प्रभुः सर, जो सात मिशंस हैं, उनमें से दो मिशंस के बारे में मैंने बताया है कि यह सेफ्टी का मिशन है ...(**व्यवधान**)... और यह रेवेन्यू का है। इसी तरह से बाकी के पाँच मिशंस हैं। हमने सातों मिशंस के ऊपर सेटअप करने की शुरूआत की है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इन मिशंस की क्या आवश्यकता है। सर, रेलवे में अलग-अलग सर्विसेज़ के लोग आते हैं और बहुत समय से हमने यह सोचा है कि इसकी वजह से compartmentalization हो गया है। Compartmentalization होने की वजह से uniformity of action होने में तकलीफ आती है, इसलिए हमने इन सातों मिशंस के ऊपर काम करने की शुरुआत की है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम जल्द से जल्द इन मिशंस को पूरी तरह से operationalize करेंगे।

MR. CHAIRMAN: Question No. 62 ...*(Interruptions)*...

श्री अविनाश पांडेः सर, मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है कि इसके लिए सेपरेट डायरेक्टरेट फॉर्म करेंगे या नहीं? ...(**व्यवधान**)... मंत्री जी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेशः सर, सवाल सीधा है, जवाब सीधा आना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेश प्रभुः मैं आपको बताता हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती रजनी पाटिलः सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पुट-अप कर दिया है।

MR. CHAIRMAN: You give answer to the hon. Member to clarify his doubts.

New farming practice

*62. SHRIMATI RAJANI PATIL: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) whether a new farming practice has been developed in the country to increase the productivity of land and to lower the water and other farm inputs in cultivation of crops; and

(b) whether the existing problems like water scarcity, high energy usage and environmental degradation would adequately be taken care of and thus crop yield would substantially be increased?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI RADHA MOHAN SINGH): (a) and (b) A Statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) Yes Sir, the Indian Council of Agricultural Research through its research institutions and All India Coordinated Research Projects/Network projects/Consortia Research Platforms with wide network of cooperating centres and State Agricultural Universities has developed cost effective, eco-friendly, socially acceptable scientific farming

practices; namely improved cultivars/planting materials/breeds, crop diversification, resource conservation technologies (zero tillage, laser leveling, bed planting, system of rice intensification, direct Seeding of rice) integrated water management, participatory watershed management for rainfed agriculture, micro irrigation, soil test based balanced and integrated nutrient management, enriched composting, vermi composting, bio-fertilizers, integrated pest management, organic farming, cost effective land reclamation technologies, climate resilient agriculture, low cost energy efficient farm implements and machinery to improve productivity of land, water and other farm inputs in cultivation of crops. These scientific farming practices are being popularized through various programmes namely National Food Security Mission (NFSM), Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY), National Horticulture Mission (NHM), Bringing Green Revolution to the Eastern Region of India (BGREI), National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA), National Mission on Agricultural Mechanization, National Mission on Oilseeds and Oil Palm (NMOOP), National Mission on Soil Health Card, Prime Minister's Krishi Sinchai Yojana (PMKSY), Parampragat Krishi Vikas Yojana (PKVY).

(b) Yes Sir, the existing problems like water scarcity, high energy usage and environmental degradation are adequately addressed. The Council recommends use of these practices in integrated farming system mode. The improved farming systems have been tested in different locations and found to increase crop and water productivity substantially over the conventional farming systems.

श्रीमती रजनी पाटिलः सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहूंगी कि जो नई टेक्नोलॉजी है, उसमें cost of cultivation और पानी का उपयोग, इन दोनों चीज़ों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसकी वजह से किसान की खेती की लागत ज्यादा और नफा कम होने का गणित बन रहा है। इससे उनको न के बराबर फायदा है। चाहे ड्रिपिंग हो, फर्टिलाइजर्स हों, ट्रैक्टर्स हों या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इनमें किसानों की बहुत बड़ी लागत लगती है। सरकार ने बाकी सारा विवरण दिया है, लेकिन मैं यह जानना चाहती हूं कि किसानों का नेट प्रॉफिट ज्यादा हो, उसके लिए क्या सरकार ने drought resistant और कम लागत लगने वाली क्रॉप्स का नियोजन किया है?

श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरियाः सभापति महोदय, सम्माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह इस बारे में है कि कम पानी में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कैसे हो सकता है? इसके ऊपर आईसीएआर ने बहुत अध्ययन किया है और नई-नई वेराइटीज़ डेवलप की हैं। फसलों में जो brown blotch नामक बीमारी पैदा हो रही थी, उसके लिए वह हाइब्रिड-6129 पर रिसर्च करके फसलों में प्रतिकारक शक्ति पैदा करने के संबंध में काम कर रहा है और इसे पंजाब और तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया है। दूसरा, बासमती नम्बर वन है। उसमें भी बहुत बीमारियां आ रही थीं, जिनके लिए प्रतिकारक क्षमता विकसित करने का भी काम किया जा रहा है और वह वेराइटी दिल्ली, पंजाब, जम्मू-

कश्मीर, उत्तराखंड में डेवलप हुई है। इसी प्रकार धान की 203 और 204 वैराइटी है। जहां जमीन लवणीय होने के कारण दूसरी वेराइटी में कम प्रोडक्शन हो रहा था, वहां इन वेराइटीज़ को डेवलप किया गया है और अब वहां बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। इसके आधार पर बहुत नई-नई वेराइटीज़ डेवलप की गई हैं। इसी प्रकार, drip irrigation, sprinkler irrigation हैं, जिनके बारे में "Per drop more crop" कहा जाता है। इस प्रकार, कम पानी में ज्यादा प्रोडक्शन कैसे हो सकता है, इस आधार पर हमने नई-नई वेराइटीज़ डेवलप की हैं।

श्रीमती रजनी पाटिलः सर, प्रोफेसर स्वामीनाथन की रिपोर्ट की हर बार चर्चा होती है और यह कहा जाता है कि उनके अनुसार डेढ़ गुना एमएसपी दी जानी चाहिए। प्रधान मंत्री ने यह कहा भी है कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, लेकिन जमीनी हक़ीकत यह है कि किसानों की आमदनी न के बराबर है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि जो कृषि विकास दर थी, वह यूपीए के समय में ज्यादा थी, जो अब 0.2 हो गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ऐसे कौन से उपाय करने जा रही है, जिनमें किसान की आमदनी दोगुनी करने की कोशिश की गई है? हमारे कृषि मंत्री जी गन्ने के बारे में बार-बार उल्लेख करते रहते हैं। आपके माध्यम से ही मैं यह भी पूछना चाहती हूं कि वे गन्ने के लिए कौन सी व्यवस्था करने जा रहे हैं? गन्ने की क्रॉप तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि भारत दुनिया में ऐसा दूसरे नम्बर का देश है, जो शुगर एक्सपोर्ट करता है। मैं जानना चाहती हूं कि गन्ने की क्रॉप के लिए आप ऐसी कौन सी योजना शुरू करेंगे, जिसके माध्यम से कम पानी में गन्ने का प्रोडक्शन हो सके?

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट के संबंध में समर्थन मूल्य के विषय में माननीय सदस्य ने जो चर्चा की है, उसके संबंध में मैं उनके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि सन् 2004 में आयोग बना था और 2007 में उसकी रिपोर्ट आयी थी, जिसमें उन्होंने 200 से ज्यादा सिफारिशें की थीं। उस समय, सन् 2007 में जो सरकार थी, उसने उसमें से बहुत सी सिफारिशों को माना। उसने इस सिफारिश को इसलिए नहीं माना कि इससे बाज़ार में विकृति आएगी। इसीलिए सन् 2007 में सरकार ने जो किसान नीति बनायी, उसमें इस विषय को छोड़ा। उसके बाद से लगातार कृषि विशेषज्ञ, जब-जब भी ये विषय आए हैं, चाहे आपकी सरकार हो या हमारी सरकार हो, उनका यह कहना है कि समर्थन मूल्य डेढ़ गुना ज्यादा बढ़ाने से बाज़ार में विकृति आएगी। उसके कुछ मान्य फॉर्मूले हैं, जिनके आधार पर आयोग सिफारिश करता है। फिर भी किसान की आमदनी बढ़े, प्रधान मंत्री जी ने यह बार-बार कहा है। चुनाव के पहले भी कहा है कि उसका मुनाफा डेढ़ गुणा, दो गुणा हो और आज मैं भी कह रहा हूं। इसके लिए जो जरूरी कदम होने चाहिए ...(**व्यवधान**)... उत्पादन बढ़े, इसके लिए जो जरूरी कदम हैं, उनके बारे में सुनिए।

श्री नरेश अग्रवालः आपके manifesto में था। ...(**व्यवधान**)...

श्री राधा मोहन सिंहः जी, मैं बोल रहा हूं। डेढ़ गुणा नहीं, मैं तो दो गुणा बोल रहा हूं कि दो गुणा बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी था, जिस पर ध्यान देना चाहिए था, वह था - हर खेत को पानी। माननीय सदस्य शरद यादव जी यहां नहीं हैं, परसों भी इस चर्चा हुई थी कि हर खेत को पानी मिले तो उत्पादन बढ़ेगा, इसीलिए सरकार ने प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना चलायी है।

उसके संबंध में मैंने उस दिन भी चर्चा की थी कि उत्पादन बढ़ाने के लिए हर खेत को पानी मिले। आपके ध्यान में होगा, 89 बड़ी परियोजनाएं 20-25 बरस से पेंडिंग हैं। छोटी योजनाओं की संख्या तो आदरणीय शरद जी काफी बड़ी बता रहे थे। उनको मिशन मोड में पूरा करने के लिए इस बार प्रावधान किया गया है कि इस वर्ष कम से कम 23 परियोजनाओं को पूरा करें और सन् 2018 आते-आते 40 परियोजनाओं को पूरा करें। इस वर्ष के लिए 12,700 करोड़ रुपए दिए गए हैं और 20,000 करोड़ रुपए का नाबार्ड के द्वारा कॉरपस फंड बनाया गया है। दूसरा, इनपुट कॉस्ट कम हो, लागत कम हो, इसके लिए आपके ध्यान में होना चाहिए कि हर किसान को Soil Health Card देने की योजना शुरू हुई है क्योंकि उसको पता नहीं होता कि कितनी खाद देनी है, कौन सी दवा देनी है। वे अंधाधुंध डालते रहते हैं जिससे उनका खर्चा बढ़ता है, इसलिए Soil Health Card की योजना शुरू की गई है। फिर जैविक खेती, जिसमें लागत बहुत कम होती है, उसको भी प्रोत्साहित किया गया है। पहली बार 2015-16 में 300 करोड़ रुपए राज्यों को दिए गए और इस वर्ष, 2016-17 में भी 300 करोड़ रुपए राज्यों को दिए गए हैं। हम राज्यों को बधाई देंगे कि उन्होंने क्लस्टर पैमाने पर ...(**व्यवधान**)... दो गुणा करने के बारे में आपका सवाल है। मैं वही बता रहा हूं कि लागत कम करने ...(**व्यवधान**)...

श्री राज बब्बर: उनका गन्ने के संबंध में स्पेसिफिक सवाल है।

श्री राधा मोहन सिंह: उन्ही का सवाल है कि दो गुणा कैसे करेंगे, डेढ़ गुणा कैसे करेंगे, मैं उसी के बारे में बता रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please let us not get into an argument. Just answer the question.

श्री राधा मोहन सिंह: आप मेरी बात सुनिए। आपने प्रश्न पूछा है कि कैसे दो गुणा करेंगे, मैं उसी के बारे में बता रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... इसी तरह से कटाई के बाद जो नुकसान होता है, उसको रोकने के लिए क्या किया जाए? उत्पादन के बाद और खपत के बीच में उसका जो नुकसान होता है, उसको कम करना, वैल्यू एडिशन, मूल्य वर्धन का काम और अच्छी मार्किट, उस पर भी एक सवाल है। उसके बाद वही सवाल है। जब प्रश्न आएगा, उस समय मैं आपको बताऊंगा कि उसको अच्छा दाम कैसे मिले, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? आपका दूसरा सवाल गन्ने को लेकर है।

MR. CHAIRMAN: Please let us have short answers. बहुत से supplementaries हैं, बहुत से सवाल हैं। Please give short answers.

श्री राधा मोहन सिंह: इनका दूसरा विषय था कि गन्ने के विषय में हमने कोई बात की है, गन्ने के संबंध में हमने कुछ बयान दिया है।

श्री सभापति: आप बहुत टाइम ले रहे हैं।

श्री राधा मोहन सिंह: उसके संबंध में इनका एक सवाल है। मैंने कल भी बताया था और मैं फिर कहना चाहूंगा कि गन्ने के किसान हम भी हैं। मेरा संदर्भ था कि मराठवाड़ा में जो सूखा आया है -

मराठवाड़ा हो, विदर्भ हो - वहां सूखा पड़ा है। इस वर्ष राजस्थान के कई इलाके हैं, जहां ज्यादा वर्षा हुई है। सूखा है - इस बात से हम सहमत हैं, लेकिन ऐसी स्थिति वहां पर क्यों आयी, इसके संबंध में कुछ विशेषज्ञों की यह राय है कि जो बांध बनाए गए हैं ... उस पर ज्यादा खपत हुई, इस पर अलग से चर्चा होनी चाहिए, यह मेरा विषय था। गन्ना किसानों के विषय में मेरा अलग से कुछ नहीं था।

श्री भुपेन्द्र यादवः माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में पूर्वी लिखा है Bringing Green Revolution on the Eastern Region and National Mission for Sustainable Agriculture. ये जो दो मिशन हैं, इन दोनों मिशनों को लागू करते समय मैं पूछना चाह रहा हूं, जो अभी आर्थिक समीक्षा में भी आया था कि कृषि में लागत बहुत ज्यादा हो गई है और ऐसे में कम से कम पूर्वी भारत में, विशेष रूप से बिहार और झारखंड में किसान उत्पादन करने के बाद भी sustain नहीं कर पा रहा है, क्या इसके लिए कृषि मंत्रालय ने कोई योजना बनाई है?

श्री राधा मोहन सिंहः सर, दूसरी "हरित क्रांति" है जिसका एक केन्द्र पूर्वी भारत है। हमारी सरकार इसको जैविक खेती ओरिएंटेड करके मिशन मोड में यह काम कर रही है ताकि सतत उत्पादकता बनी रहे।

दूसरा, अभी 2015-16 में जहां पर धान की रोपाई नहीं हो पाती है, वहां पर भूमि का उपयोग करने के लिए दलहन और तिलहन मिशन के तहत अलग से राशि दी जा रही है। इस बार भी बजट में 500 करोड़ रुपये अलग से दिए गए हैं, इनका भी उपयोग किया जा रहा है। हमने इंटिग्रेटेड फार्मिंग 1990 में शुरू की थी, इसमें जल का कम उपयोग होता है और उत्पादकता भी बढ़ती है, किसान की आमदनी भी बढ़ती है। आज की तारीख में हमारे जो कृषि अनुसंधान संस्थान और विश्वविद्यालय हैं, ये आज से ही नहीं, पहले से काम कर रहे हैं, आदरणीय शरद पवार जी के समय से काम कर रहे हैं, यह प्रदर्शन इसके अंदर होता था, आईसीएआर की लैब में, यूनिवर्सिटी के फील्ड में होता था, उसको जमीन तक ले जाने की प्रक्रिया तेज हुई है और आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि डेढ़ लाख मिलियन हैक्टेयर में इंटिग्रेटेड फार्मिंग हो रही है और इसका बहुत बड़ा हिस्सा पूर्वी भारत में ही है। कई ऐसी योजनाएं हैं, जिनका क्रियान्वयन उन राज्यों में हो रहा है

श्री शरद पवारः सभापति महोदय, प्रश्न के जवाब में बताया गया कि जो कुछ कदम उठाते हैं, उसमें एक चीज़ पर ध्यान दिया गया है कि पानी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कम पानी से खेती कैसे हो सकती है। इस बारे में कुछ अनुसंधान अपने ही देश के Indian Council for Agricultural Research में हुआ है। इस संबंध में drought resistant character कुछ क्रॉप्स में डेवलप करने के लिए जेनेटिकली बदलाव लाने की भी बात थी और इस क्षेत्र में कुछ काम किया गया। बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया कि यह काम नहीं करना चाहिए और भारत सरकार की एनवायर्नमेंट मिनिस्ट्री ने भी एक अलग राय ले ली। मैंने प्रधान मंत्री जी को और एनवायर्नमेंट मिनिस्टर साहब को लिखा था कि drought resistant character develop करने के बारे में आज हमारे यहां रिसर्च हुई है और उनका ट्रायल लेने की भी इजाजत नहीं है, यह बात ठीक नहीं है। साइंटिस्ट ने काई नया प्रोडक्ट डेवलप किया, तो उसका ट्रायल लेने की आवश्यकता है। जो ट्रायल पर पाबंदी है, उसको हटाइए। मुझे खुशी है

कि प्रधान मंत्री जी ने और एनवायर्नमेंट मिनिस्टर ने मुझे लिखा कि ट्रायल्स के लिए हम इजाजत देंगे, यह अच्छी बात है। जब भारत सरकार ट्रायल्स के लिए इजाजत दे रही है और देश में एक या दो राज्यों को छोड़कर बाकी सब राज्य ट्रायल के लिए इजाजत नहीं देते हैं, तो मैं कृषि मंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो राज्य ट्रायल की इजाजत नहीं देते हैं, क्या आप उनको ट्रायल की इजाजत देने की रिक्वेस्ट राज्यों से करेंगे और उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे? अगर ऐसा नहीं किया तो साइंटिस्ट कम्युनिटी में नाराज़गी पैदा हो जाएगी।

श्री राधा मोहन सिंहः सभापति महोदय, मैं आदरणीय शरद पवार जी के विचार से सहमत हूं और निश्चित रूप से इस दिशा में आगे बात करूंगा।

प्रो. राम गोपाल यादवः सभापति महोदय, क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में यह लगभग तय हो चुका है कि अगर एक डिग्री टैम्परेचर बढ़ जाएगा, तो प्रोडक्शन लगभग 15-16 परसेंट कम हो जाएगा। इस बार उत्तर प्रदेश में देखा है, मैंने अपनी ही खेती में देखा है कि यह production 15-20 परसेंट कम हुआ है। कई बार संसद की क्रय संबंधी स्थायी समिति ने यह रिपोर्ट दी कि जो आपकी संस्थाएं हैं, Indian Council of Agricultural Research और agricultural universities, वे इसको ध्यान में रखते हुए इस तरह के कुछ ऐसे नए seeds की रिसर्च करें, ऐसे seeds तैयार करें, जिसके लिए पानी की कम जरूरत हो, क्योंकि पानी ही सबसे बड़ी समस्या है। आज जल स्तर को गिरने से रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जा रहा है। नए seeds, जिनके लिए पानी की कम जरूरत हो, वे तैयार नहीं किए जा रहे हैं। क्या आपने कभी इस बात की समीक्षा की कि agricultural universities ने या ICAR ने इस तरह के कोई नए seeds निकाले हैं, जिनके लिए पानी की कम जरूरत पड़े और पानी की कमी की वजह से production पर जो असर पड़ रहा है, उसको दूर किया जा सके?

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, जलवायु उत्पन्न कूलन कृषि पर राष्ट्रीय innovation कार्यक्रम की शुरूआत 11वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इस 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी इसके लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इस पहल का उद्देश्य राजनीतिपरक अनुसंधान और technology प्रसार के माध्यम से जलवायु परिवर्तन एवं जलवायु संवेदनशीलता के प्रति भारतीय कृषि की अनुकूलता को बढ़ाना है। परियोजना के चार संघटक हैं, इसके चार भाग हैं। एक तो रणनीतिपरक अनुसंधान है, दूसरा देश के 150 सर्वाधिक संवेदनशील ज़िलों में सर्वश्रेष्ठ कृषि टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन, तीसरा क्षमता निर्माण और चौथा प्रायोजित अनुदान, उनको अनुदान देना है। इस टेक्नोलॉजी प्रसार के लिए 27 राज्यों के 100 जिलों में काम शुरू कर दिया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है। जहां तक सूखा और जलवायु परिवर्तन रोधी बीजों का सवाल है, मैं बताना चाहूंगा कि 2010 में 151 किस्में जारी की गई थीं। चूंकि इसकी शुरूआत 11वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी और बरसों बाद, यहां तक आते-आते मेरे पास इसका विवरण है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, चाहे बाढ़ हो, वर्षा हो या गरमी हो, उस संबंध में बताना चाहता हूं कि अभी तक 601 किस्में जारी कर दी गई हैं, जो कि फील्ड में हैं।